

एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी

बनाम

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य।

जुलाई 15, 1991

[टी। कोचू थोमेन और आर.एम. साह, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1948: धारा 10, 14, 17, 33-मध्यस्थ क्षेत्राधिकार-विवाद -पंचाट के भीतर नहीं -पंचाट के बाहर निर्णय लिया जाना -ऐसे पंचाट की अस्पष्टता -बाह्य साक्ष्य स्वीकार करके हल किया जाना -क्षेत्राधिकार का विस्तार मध्यस्थ के द्वारा नहीं किया जा सकता-वह अनुबंध में पुनरावृत्ति से बंधा हुआ है -कानून या अनुबंध के प्रावधानों की सचेत अवहेलना -क्या यह एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और पंचाट को खराब करता है।

नागार्जुनसागर बांध के निर्माण के संबंध में एक समझौते के तहत सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के संबंध में प्रतिवादी राज्य और ठेकेदार के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए। मध्यस्थ अंपायर नियुक्त किया गया और पार्टियों ने उसके समक्ष अपनी दलीलों और दस्तावेजों पर ध्यान दिया। लागत और ब्याज के सामान्य दावा के अलावा 15 दावे थे। अंपायर द्वारा दिया गया पंचाट सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सिविल कोर्ट ने पंचाट को

न्यायालय का नियम बना दिया और डिक्री की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पंचाट के संदर्भ में एक डिक्री पारित की।

अपील पर, उच्च न्यायालय ने तीन दावे के संबंध में डिक्री को इस आधार पर रद्द कर दिया कि दावा का समर्थन पार्टियों के बीच समझौते से नहीं किया गया था और मध्यस्थ दावा को देने में अनुबंध से परे चला गया, और तीन अन्य दावा के संबंध में डिक्री की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के फैसले से दोनों ठेकेदार व्यथित हैं और राज्य सरकार ने विशेष अनुमति द्वारा अपील को प्राथमिकता दी। ठेकेदार की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि अंपायर ने एक नॉन-स्पीकिंग पंचाट दिया और अनुबंध के संदर्भ के अलावा पंचाट के हिस्से के रूप में किसी भी दस्तावेज़ को शामिल नहीं किया, कानूनन पंचाट के साथ न्यायालय को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, और उच्च न्यायालय ने एक नॉन-स्पीकिंग पंचाट में हस्तक्षेप करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। -बोलने का पंचाट. राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि तर्क की संक्षिप्तता के बावजूद, मध्यस्थ ने एक सकारण निर्णय दिया था, लेकिन कानून तथ्य की स्पष्ट त्रुटियां थी और उसने अनुबंध के विपरीत निर्णय दिया, जो उसकी क्षेत्राधिकार सीमा से अधिक हो गया

न्यायालय द्वारा संविदाकार की अपील को खारिज करते हुए राज्य सरकार की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई ।

अभीनिर्धारित: 1. मध्यस्थ मनमाने ढंग से, अतार्किक ढंग से या अनुबंध से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। उसका एकमात्र कार्य अनुबंध की शर्तों में मध्यस्थता करना है। अनुबंध के तहत पार्टियों ने उसे जो कुछ दिया है, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि वह अनुबंध की सीमा से बाहर जाता है, तो उसने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया है। लेकिन यदि वह अनुबंध के मापदंडों के भीतर रहा है और अनुबंध के प्रावधानों का अर्थ लगाया है, तो उसके पंचाट में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसने पंचाट के लिए दिए कारणों में स्पष्ट त्रुटि ना की हो। [938 ए-बी]

2. एक मध्यस्थ जो अनुबंध की स्पष्ट अवहेलना करते हुए कार्य करता है अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। उसका अधिकार अनुबंध से प्राप्त होता है और मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होता है जो एजेंसी के कानून की एक विशेष शाखा से प्राप्त सिद्धांतों का प्रतीक है। वह कदाचार करता है यदि वह अपने पंचाट के द्वारा वह समझौते से बाहर किए गए मामलों का निर्णय करता है, जानबूझकर अनुबंध से हटना न केवल उसके अधिकार की अवहेलना अथवा उसकी ओर से कदाचार को दर्शाता है, बल्कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान माना जा सकता है। कानून या अनुबंध के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना, जिससे उसने अपना अधिकार प्राप्त किया है, पंचाट को खराब कर देता है। [938 सी-ई]

मस्टिल एंड बॉयड्स कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दूसरा संस्करण, पेज 64;
हैल्सबरी के इंग्लैंड के नियम, खंड II, चौथा संस्करण, पैरा 622, संदर्भित

3. मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के बारे में विवाद पंचाट के भीतर का कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसका निर्णय पंचाट के बाहर किया जाना होता है। एक अंपायर या मध्यस्थ किसी ऐसे प्रश्न का निर्णय करके, जो पार्टियों द्वारा उसे नहीं भेजा गया है, या अनुबंध से भिन्न किसी अन्य तरीके से निर्णय लेकर अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है। वह यह नहीं कह सकता कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि अनुबंध में क्या कहा गया है। वह इससे बंधा हुआ है। इसे उसका निर्णय इसके अनुसार करना होगा। वह इसकी सीमा से बाहर यात्रा नहीं कर सकता। यदि उसने ऐसा करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, तो उसका पंचाट रद्द कर दिया जाएगा। [938 ई-एफ]

अटॉर्नी जनरल ऑफ मैनिटोबा बनाम केली और अन्य के लिए,
[1922] 1 एसी 268, संदर्भित.

4.1. मामलों के साक्ष्य जो पंचाट से प्रकट नहीं होते, वह यह तय करने के लिए स्वीकार्य होगा कि क्या मध्यस्थ ने अनुबंध की सीमा से बाहर यात्रा की और इस प्रकार वह अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। यह देखने के लिए कि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र क्या है, न्यायालय यह देख सकता है कि उसके समक्ष क्या विवाद प्रस्तुत किया गया है। यदि यह

निर्णय से स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय बाहरी स्रोतों का सहारा ले सकता है। न्यायालय पार्टियों के हलफनामों और दलीलों को देख सकता है; न्यायालय स्वयं समझौते को देख सकता है। [939 ए-बी]

बंज एंड कंपनी बनाम देवर एंड वेब, [1921] 8 एल. आई. एल.प्रतिनिधि. 436 (के.बी.), संदर्भित ।

4.2. यदि मध्यस्थ द्वारा अनुबंध के निर्वचन में कोई त्रुटि होती है, यह त्रुटि उसके अधिकार क्षेत्र की एक त्रुटि है। लेकिन अगर वह अनुबंध के बाहर भटकता है और उन मामलों से निपटता है जो उसे आवंटित नहीं किए गए हैं तब वह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि करता है। उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी त्रुटि पंचाट के बाहर की सामग्री से स्थापित की जा सकती है। ऐसे मामलों में बाहरी साक्ष्य स्वीकार्य हैं क्योंकि विवाद ऐसा कुछ नहीं है जो अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होता है या अनुबंध के निर्वचन पर निर्भर करता है या पंचाट के भीतर निर्धारित किया जाता है। क्षेत्राधिकार के संबंध में विवाद एक ऐसा मामला है जो पंचाट के बाहर है या पंचाट में इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसके बाहर है। ऐसे मामलों में, पंचाट की अस्पष्टता को बाहरी साक्ष्य को स्वीकार करके हल किया जा सकता है। विवाद की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे पंचाट में प्रकट होने वाली बातों से बाहर और स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए

ऐसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि को पंचाट से बाह्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। [939 सी-एफ)

मेसर्स अलोपी प्रसाद एंड संस लिमिटेड बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया, [1960) 2 एससीआर 793; भारत संघ बनाम किशोरी लाल, एआईआर 1959 एससी 1362; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, [1984) 4 एससीसी 679; जीवराजभाई बनाम चिंतामनराव, एआईआर 1965 एससी 214; गोबर्धन दास बनाम. लछमी राम, एआईआर 1954 एससी 689 और थावरदास बनाम भारत संघ, एआईआर 1955 एससी 468 पर भरोसा किया गया।

बंज एंड कंपनी बनाम देवर एंड वेब, [1921) 8 एल. आई. एल. प्रतिनिधि 436 (के.बी.); क्रिस्टोफर ब्राउन लिमिटेड बनाम जेनोसेंसचाफ्ट ओस्टररेइचिशर, [1954) 1 क्यूबी 8; रेक्स बनाम फ़ुलहम, [1951] 2 के.बी. एल; फ़ॉकिंगम बनाम विक्टोरियन रेल" वेज़ कमीशन, [1900] ए.सी. 452; रेक्स बनाम ऑल सेंट्स, साउथेम्प्टन, [1828] 7 बी. एंड सी. 785; लैंग, सन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ईस्टचीप ड्राइड फ़्रूट कंपनी, [1961] 1 एलआई. एल. प्रतिनिधि. 142, 145 (क्यू.बी.); डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, [1978] 2 एलआई. एल. प्रतिनिधि. 223 (सी.ए.); हेमैन बनाम डार्विन्स लिमिटेड।, [1942] ए.सी. 356; ओमानहेन बनाम चीफ ओबेंग, एआईआर 1934

पी.सी. 185; एफ.आर. अबशालोम लिमिटेड बनाम ग्रेट वेस्टर्न (लंदन) गार्डन विलेज सोसाइटी, लिमिटेड, [1933] एसी 592 (एचएल) और एम. गोलोडेट्ज़ बनाम श्रियर एवं अन्य, [1947] एसओएलआई. एल.रेप. 647, संदर्भित।

5. मौजूदा मामले में, अंपायर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले का फैसला किया। उन्होंने अनुबंध की सीमाओं का उल्लंघन किया। वह निर्धारित क्षेत्र से काफी बाहर भटक गया। वह आवंटित कार्य से काफी भटक गए। उनकी गलती अनुबंध को गलत तरीके से पढ़ने या गलत अर्थ निकालने या गलतफहमी के कारण नहीं हुई, बल्कि सहमति से परे जाकर कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई। यह त्रुटि उनके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती थी क्योंकि उन्होंने खुद से गलत सवाल पूछा, अनुबंध की अवहेलना की और अपने अधिकार से अधिक का पंचाट दिया। कई मामलों में, यह पंचाट अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था। अंपायर ने अनुबंध की सीमाओं और स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अनुचित, अतार्किक और मनमौजी तरीके से काम किया। उन दावा को देने में, जो अनुबंध के प्रावधानों के पूरी तरह से विरोध में हैं, जिसके लिए उन्होंने उन्हें अनुमति देने में विशिष्ट संदर्भ दिया था, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं और अनुबंध की सीमाओं की स्पष्ट रूप से अवहेलना करके खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया और कदाचार किया है, जिससे उन्होंने अपना

अधिकार प्राप्त किया था। इस प्रकार समझोते की सीमा से परे जाकर कार्य किया। [940 ए०डी]

एम.एल. सेठी बनाम आर.पी. कपूर, एआईआर 1972 एससी 2379; प्रबंधन निदेशक, जे. और के. हस्तशिल्प बनाम मिस। गुड लक कार्पेट, आकाशवाणी 1990 एससी 864 और आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. आर. वी. रायनिम, आकाशवाणी 1990 एससी 626, पर निर्भर।

एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम विदेशी मुआवजा आयोग, [1969] 2 एससी 147; पर्लमैन बनाम हैरो स्कूल के रखवाले और गवर्नर, [1979] 1 क्यू.बी. 56 और ली बनाम शोमेन गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, [1952] 2 क्यू.बी. 329, संदर्भित.

मस्टिल/ एंड बॉयड्स कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दूसरा संस्करण, पी। 641 एफ और हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, वॉल्यूम। 2, पैरा 622, संदर्भित।

6.1. मौजूदा मामले में, अनुबंध में वास्तव में इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। नैपासलैब्स के लिए दावा संख्या III या पानी की अतिरिक्त लीड के लिए दावा संख्या VI या नहर ढलानों को समतल करने के लिए दावा संख्या IX या श्रम शुल्क में वृद्धि के लिए दावा संख्या II के तहत किसी भी वृद्धि का भुगतान, अनुबंध द्वारा निर्धारित फॉर्म के नियमों से अन्यथा था। अंपायर ने पूरी तरह से अनुमेय क्षेत्र के बाहर यात्रा की और इस प्रकार

उन दावा के तहत पंचाट देने में अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया। यह उसके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाने वाली त्रुटि है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि मध्यस्थ ने उपरोक्त दावा को देने में अनुबंध के विपरीत काम किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय श्रम शुल्क में वृद्धि से संबंधित दावा संख्या II के संबंध में डिक्री की पुष्टि करने में गलत था क्योंकि आइटम 35 के तहत एक विशिष्ट फॉर्मूला निर्धारित किया गया था, और अंपायर का कार्य इसके अनुसार एक पंचाट देना था। उसे इसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। [937 सी-डी; 936 एफ)

जीवराजभाई उजमशी शेठ और अन्य बनाम चिंतामन राव बालाजी और अन्य, एआईआर 1965 एससी 214, पर भरोसा किया।

6.2. 'मशीनरी के फालतू किराया शुल्क की वापसी' और विभाग की मशीनरी के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए भुगतान से संबंधित दावा संख्या IV और और भविष्य के लिए भी दिशा-निर्देश' को मध्यस्थ द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी और उनके निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से बरकरार रखा गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा आपूर्ति की गई मशीनरी के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए अतिरिक्त उच्च शुल्क के लिए सरकार ठेकेदार को मुआवजा देने के लिए बाध्य थी। [937 ई-एफ)

6.3. 'रेत परिवहन' से संबंधित दावा संख्या VI1(4) के संबंध में मध्यस्थ यह कहने में सही था कि समझौते के पृष्ठ 59 पर विवरण (ए) के आइटम नंबर 5 के लिए डीजल तेल की आवश्यकता 0.35 लीटर के रूप में ली जानी चाहिए, न कि 0.035 के रूप में और तदनुसार मूल्य समायोजन किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस दावा को सही ठहराया।
[937 जी-एच; 938 ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 338-339/1991

हैदराबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.12.85 से 1984 के ओएमए नंबर 456 और 1984 के सीआरपी नंबर 2743 में उच्च न्यायालय।

साथ

सिविल अपील संख्या 2692-930 / 1991

के.आर. चौधरी अपीलकर्ता की ओर से ।

के. माधव रेड्डी, जी. प्रभाकर, टी.वी.एस.एन. चारी (सं.पु.)
उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

थॉमेन. जे. एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 7071-72 / 1986 में स्वीकृति
दी गई

ये अपीलें ओ.एम.ए. क्रमांक 456 / 1984 एवं सी.आर.पी. नंबर 2743 / 1984 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आम फैसले के खिलाफ लायी गयी हैं। उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के सिविल कोर्ट के प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के मूल दीवानी दावा नंबर 174 / 1983 और ओ. पी. नंबर 49 / 1983 में पारित आम फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया, जिसके तहत उन्होंने अंपायर (इसके बाद 'अंपायर' या 'मध्यस्थ' के रूप में संदर्भित) के पंचाट को अदालत का एक नियम बनाया और दावा के संदर्भ में ब्याज सहित एक डिक्री पारित कर डिक्री की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के साथ मूल राशि प्रदान करने का फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय ने दावा संख्या III, VI और IX के संबंध में डिक्री को रद्द कर दिया और अन्य दावा के लिए डिक्री की पुष्टि की। 1991 की मुख्य अपील संख्या 338 और 339 एस.एल.पी. (सी) 1986 की संख्या 1573 और 1574 एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंपनी (इसके बाद 'ठेकेदार' के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न हुई हैं। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किये गये फैसले को चुनौती दी गयी है

दावा संख्या III, VI और IX के संबंध में सिविल कोर्ट की डिक्री से उत्पन्न होने वाली अन्य अपीलें एस.एल.पी. (सी) 1986 की संख्या 7071 और 7072 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गयी हैं और वे दावा संख्या II, IV

और VII(4) के संबंध में सिविल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हैं।

उच्च न्यायालय ने दावा संख्या III, VI और IX को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वो दावा पार्टियों के बीच समझौते द्वारा समर्थित नहीं थे और मध्यस्थ ने उन दावा को अनुबंध के परे जाकर दियाथा। जबकि उच्च न्यायालय के फैसले का वह हिस्सा सरकार द्वारा समर्थित है, ठेकेदार का कहना है कि उच्च न्यायालय नान स्पीकिंग दावा में हस्तक्षेप करके अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया। सरकार उच्च न्यायालय के फैसले जिसमें उसने दावा संख्या II, IV और VII(4) के संबंध में सिविल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की है को इस आधार पर चुनौती देती है कि मध्यस्थ द्वारा दिया गया दावा अनुबंध द्वारा पूरी तरह से असमर्थित है।

श्री ए.बी. दीवान का ठेकेदार की ओर से तर्क है कि अंपायर ने नान स्पीकिंग दावा दिया। अनुबंध के संदर्भ के बावजूद, उन्होंने दावा के हिस्से के रूप में किसी भी दस्तावेज को शामिल नहीं किया। वकील का मानना है कि इन परिस्थितियों में कानून ऐसे दावा में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता है।

दूसरी ओर सरकार की ओर से उपस्थित श्री के. माधव रेड्डी का कहना है कि अंपायर ने दावा के सम्बंध में सकारण पंचाट दिया और उन्होंने पंचाट में उन दावा को जारी करने के कारण बताए। वकील का

कहना है कि यह सच है कि अंपायर ने अनुबंध के प्रावधानों और दावा देने के अपने कारणों का केवल संक्षिप्त संदर्भ दिया था। लेकिन उनके तर्क की संक्षिप्तता के बावजूद, उन्होंने पर्याप्त रूप से स्पष्ट बात की है जिसके परिणामस्वरूप कानून और तथ्य की त्रुटियां दावा को देखने मात्र से स्पष्ट हो गई हैं, जिससे पता चलता है कि अंपायर ने कोट्रेक्ट के विपरीत और असमर्थित कार्य किया, जो उसकी क्षेत्राधिकार सीमा से अधिक हो गया। उनका कहना है कि अंपायर ने अनुबंध का उल्लेख केवल मामले को सुनने और विवाद को सुलझाने के अपने अधिकार को बताने या सुनाने के उद्देश्य से नहीं किया है, बल्कि इसे दावा के एक हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए किया है। ऐसा करने में, उसने न केवल अनुबंध की गलत व्याख्या की, बल्कि उससे पूरी तरह से परे जाकर और अनुबंध की परवाह किए बिना और उससे स्वतंत्र होकर एक दावा देकर अनुबंध का उल्लंघन किया। दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने वाद के समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया गया है।

यह पंचाट नागार्जुनसागर बांध के निर्माण के संबंध में दिनांक 20.1.1981 (बाद में पूरक) समझौते के तहत सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए सरकार और ठेकेदार के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में बनाया गया था। पार्टियों ने मध्यस्थ/अंपायर के समक्ष अपनी दलीलें और दस्तावेज दाखिल किए। लागत और ब्याज के सामान्य दावे के अलावा 15 दावे थे।

जैसा कि पहले कहा गया है, हम केवल दावा संख्या III, VI और IX से संबद्ध हैं जो अंपायर द्वारा दिए गए दावे हैं और सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री दी गयी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, और दावा संख्या II, IV और VII(4) के साथ जो अंपायर द्वारा दिए गए थे और सिविल कोर्ट द्वारा भी और हाई कोर्ट द्वारा भी डिक्री द्वारा किये गए थे. दावों का पहला सेट क्रमशः 'नापा स्लैब पर वृद्धि'; 'पानी के लिए अतिरिक्त सीसा का भुगतान'; और, 'नहर की ढलानों के समतल होने और इसके परिणामस्वरूप सड़क मार्ग के रूप में उपयोग किए जाने वाले किनारों की ऊपरी चौड़ाई में कमी के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय हैं।' दावों का दूसरा समूह क्रमशः 'श्रम वृद्धि' ; 'मशीनरी के अतिरिक्त किराया शुल्क की वापसी'; और, 'रेत परिवहन' से संबंधित है।

अंपायर ने विवाद की पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद 16.12.82 को विवाद का फैसला करने के लिए रेफरेंस किया और पार्टियों के बीच संबंधित समझौते से दावों की श्रृंखला का निपटारा किया गया। दावा संख्या III के संबंध में, वे कहते हैं:

"मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं और पंचाट देता हूं और प्रतिवादी को निर्देश देता हूं कि वह अनुबंध अनुसूची ए के आइटम 11 के तहत नपा स्लैब लाइनिंग के प्रति वर्ग

मीटर 4.25 रुपये (चार रुपये और पच्चीस पैसे) की गणना की गई नेपस्लैब की लागत में वृद्धि के लिए दावेदारों को संपूर्ण कार्य के लिए मुआवजा दे और तदनुसार भुगतान करें"।

इस पंचाट के खिलाफ सरकार द्वारा की गई मुख्य आलोचना यह है कि नापा-स्लैब की लागत या कीमत में वृद्धि के लिए अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था। श्रम, डीजल तेल, टायर और ट्यूब से संबंधित अनुबंध में वृद्धि का प्रावधान, जैसा कि उसके आइटम 35 में दिया गया है। जहां तक नापा-स्लैब का सवाल है, अनुबंध में कोई वृद्धि प्रावधान नहीं था। अनुबंध में इन स्लैब की कीमत 4.25 रुपये प्रति वर्ग निर्धारित की गई थी और उस कीमत को बढ़ाने या घटाने का कोई प्रावधान नहीं था। अनुबंध के दोनों पक्ष उस कीमत से बंधे थे और इसलिए, मध्यस्थ के पास नापा-स्लैब की कीमत में कोई वृद्धि देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अनुबंध में किसी भी प्रावधान के अभाव में, मध्यस्थ के पास वृद्धि के लिए पंचाट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। सरकार की इस दलील को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

ठेकेदार की ओर से उपस्थित श्री दीवान, नपा-स्लैब के लिए वृद्धि की अनुमति देने वाले अनुबंध के किसी भी प्रावधान का उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हैं। वह केवल अनुबंध के आइटम 35 का उल्लेख करने की स्थिति में है जो लागत में वृद्धि या कमी के लिए मूल्य समायोजन को संदर्भित करता है। वह वस्तु, जैसा कि पहले कहा गया है, विभिन्न मामलों जैसे डीजल तेल, श्रम इत्यादि को संदर्भित करती है, लेकिन नपा-स्लैब को नहीं। दूसरी ओर, उस आइटम के अंत में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि 'यहां दिए गए मूल्य समायोजन के अलावा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।' इसके अलावा, यह विशेष रूप से अनुबंध में प्रदान किया गया है 'ठेकेदार को मानक विनिर्देशों के अनुसार नापा-स्लैब प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। विभाग खदानों को सौंपने या नपा-स्लैब या कोई अन्य सुविधाएं खरीदने में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। उपरोक्तानुसार खदानों के चयन में परिवर्तन के कारण ठेकेदार किसी भी अतिरिक्त दर का हकदार नहीं होगा इस प्रकार आइटम 35 के बाहर आने वाले किसी भी मामले के संबंध में मूल्य समायोजन या बढ़ी हुई लागत के लिए पंचाट के खिलाफ एक विशिष्ट निषेध है।

हालाँकि, श्री दीवान का मानना है कि नॉन-स्पीकिंग पंचाट होने के कारण, न्यायालय कारणों की जाँच नहीं कर सकता है। सरकार की ओर से उपस्थित श्री माधव रेड्डी का कहना है कि पंचाट इस मुद्दे पर चुप नहीं है।

यह संक्षेप में ही सही, वाक्पटुता से बोलता है। यह केवल पंचाट के वाचन या वर्णनात्मक भाग में नहीं है कि समझौते का उल्लेख किया गया है, लेकिन दावा संख्या III के तहत पंचाट देने में समझौते को विशेष रूप से समझौते की अनुसूची ए के आइटम 11 के तहत 4.25 रुपये की दर से नपा-स्लैब पर वृद्धि के लिए भुगतान का निर्देश देकर शामिल किया गया है। इस प्रकार समझौते को पंचाट में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है, जिससे इसको देखने मात्र से स्पष्ट त्रुटि का पता चलता है और मध्यस्थ के पूरी तरह से बाहर जाने और अनुबंध का विरोध करने के कारण उसके अधिकार क्षेत्र की कुल कमी का पता चलता है। वकील का कहना है कि यह अनुबंध संबंधी प्रावधानों के किसी निर्वचन से नहीं, बल्कि केवल अनुबंध के दायरे में आने वाले मामलों को देखने से पता चलता है।

दावा संख्या VI-पानी के लिए अतिरिक्त सीसे का भुगतान।

यह मध्यस्थ का कहना है:

"मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं और प्रतिवादी को अनुसूची "ए" के आइटम 4, 5, 6, 10 और 11 के लिए समझौते में निर्दिष्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर पानी के लिए अतिरिक्त लीड के लिए 3 किलोमीटर अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश देता हूं।

इस दावे के संबंध में, श्री दीवान ने अपना तर्क दोहराया कि पंचाट कारणों के बारे में चुप है और, लिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

दूसरी ओर, श्री माधव रेड्डी का मानना है कि यह पंचाट पानी के लिए अतिरिक्त सीसे के लिए अतिरिक्त राशि के दावे को अनुमति देने के कारणों के बारे में बताता है यानी 2 कि.मी. की निर्दिष्ट लीड से अधिक 3 किलोमीटर के लिए। लेकिन वकील का कहना है कि समझौते में किसी भी लीड के लिए बिल्कुल भी भुगतान नहीं करने और किसी अतिरिक्त लीड के लिए तो बिल्कुल भी भुगतान का प्रावधान नहीं है। उन्होंने पानी को लेकर समझौते के खास प्रावधान का जिक्र किया है. उनका कहना है कि ठेकेदार को खदान सहित सभी उद्देश्यों के लिए कार्य स्थल पर पानी की आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी थी। अनुबंध में साइट पर लाए गए पानी के लिए ठेकेदार को कोई भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील का कहना है कि ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, यह बेतुका है कि मध्यस्थ को पानी

के लिए अतिरिक्त लीड के लिए अतिरिक्त राशि देनी चाहिए थी। अनुबंध में विशेष रूप से कहा गया था कि पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। सरकार ने पानी की उपलब्धता या उसके लिए देय कीमतों के संबंध में ठेकेदार को कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए, अंपायर के पास दावा संख्या VI की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्क को स्वीकार करते हुए उस दावे के संबंध में सिविल कोर्ट के फैसले को उलट दिया और कहा " स्पष्ट समझौते के मद्देनजर कि ठेकेदार को इलाज के उद्देश्य से पानी की आपूर्ति की अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, मुआवजा देना समझौते के दायरे से बाहर है और दूषित है।"

दावा संख्या IX नहर की ढलानों के समतल होने और परिणामस्वरूप सड़क के रूप में उपयोग किए जाने वाले किनारों की ऊपरी चौड़ाई में कमी के कारण हुआ अतिरिक्त व्यय।

इस दावे का हवाला देते हुए पंचाट यही कहता है:

"में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं और प्रतिवादी को आदेश देता हूं कि वह दावेदार को नहर के बाईं ओर ढलान पर नपा स्लैब लाइनिंग पर किए गए 50% काम के लिए लाइनिंग कार्य के लिए 4.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त दर पर भुगतान करे।"

ठेकेदार की दलीलों को खारिज करते हुए और सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि अनुबंध में नहर ढलानों के रखरखाव और सड़क मार्ग के रूप में उपयोग किए जाने वाले किनारों की ऊपरी चौड़ाई में कटौती के लिए किसी भी भुगतान का प्रावधान नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि बैंकों की मरम्मत करना ठेकेदार की जिम्मेदारी थी और अनुबंध में चौड़ाई में कमी या अन्यथा किसी भी राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। हाई कोर्ट का कहना है कि '...इस स्कोर पर दावे की स्वीकृति समझौते के दायरे से बाहर है और इस तरह यह दूषित है।'

जबकि ठेकेदार के वकील ने पंचाट के संबंध में कारणों के बारे में मौन रहते हुए अपनी दलीलें दोहराईं, श्री माधव रेड्डी का कहना है कि दावा

संख्या IX के तहत अनुबंध में कोई भुगतान नहीं करने का प्रावधान है। दूसरी ओर, यह विशेष रूप से बताता है

"8(ए) साइट सुविधाएं-

बैचिंग प्लांट साइट से कार्य स्थल तक पहली बार में परिवहन सड़कें विभाग द्वारा प्रत्येक बैचिंग प्लांट साइट पर साइट सर्वेक्षण के अनुसार बनाई जाएंगी। ये ढुलाई सड़कें उचित मौसम वाली सड़कें हैं जिनमें केवल धारा क्रॉसिंग पर कठिन मार्ग होते हैं। बैचिंग प्लांट क्षेत्र के भीतर हॉल सड़कों का निर्माण, विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों सहित सभी हॉल सड़कों का रखरखाव ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी। ई.एन.एस. के नियंत्रण में मौजूदा सड़कें और सड़कें परियोजना का उपयोग ठेकेदार द्वारा किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा अपेक्षित और योजना में निर्दिष्ट नहीं की गई कोई भी अन्य ढुलाई सड़क ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर बनाई जाएगी।

8.(ए) 1. किनारों का चौड़ीकरण-

सामग्री के परिवहन की सुविधा के लिए विभाग द्वारा दाएं और बाएं किनारों के लिए नहर के किनारों को क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर की चौड़ाई तक चौड़ा किया जाएगा। हालाँकि, ठेकेदार को ढुलाई सड़कों का रखरखाव करना होगा"।

अतिरिक्त व्यय के भुगतान के लिए किसी प्रावधान के अभाव में और ठेकेदार पर हॉल सड़कों के रखरखाव की एकमात्र जिम्मेदारी डालने वाले विशिष्ट प्रावधान के आलोक में, मध्यस्थ के पास 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अतिरिक्त दर पर 50% का पंचाट देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अनुबंध में खंड के तहत सख्ती से निर्दिष्ट राशि के बाहर किसी भी राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। इन परिस्थितियों में, श्री माधव रेड्डी का कहना है, जहां तक मध्यस्थ के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने का संबंध है, तो उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से न्यायसंगत था, जो उसने किया।

अब हम दावों के अन्य सेट, अर्थात् दावा संख्या II, IV और VII(4) से निपटेंगे, जिन्हें नीचे की दोनों अदालतों द्वारा सम्मानित और डिक्री किया गया था। मध्यस्थ दावा संख्या II को इस प्रकार निपटाता है:

$$V2 \frac{P1}{100} \times R = \frac{(WSI - WSO)0.10}{WSO} + \frac{(WSSI - WSSO)0.10}{WSSO} - \frac{(WUSI - WUSO)0.8}{WUSO}$$

जहाँ बनाम- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 22.10.1980 के बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित श्रम की न्यूनतम मजदूरी में वैधानिक वृद्धि के कारण देय मुआवजा।

पी-1. अनुबंध के पृष्ठ 139 पर परिशिष्ट 9 के अनुसार कार्य की प्रत्येक वस्तु का प्रतिशत श्रम घटक।

आर- समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्य की प्रत्येक मद के अंतर्गत किए गए कार्य का मूल्य।

डब्ल्यूएसओ- 11.15 (कुशल श्रम के लिए निविदा की तिथि पर लागू दैनिक न्यूनतम वेतन)

डब्ल्यूएसएसओ- 8.50 (अर्धकुशल श्रम के लिए निविदा की तिथि पर लागू दैनिक न्यूनतम वेतन)।

डब्ल्यूएसओ- 5.65 (अकुशल श्रम के लिए निविदा की तिथि पर लागू दैनिक न्यूनतम वेतन)।

डब्ल्यूएसआई- संशोधित दैनिक न्यूनतम वेतन जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षाधीन अवधि के लिए कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है।

डब्लूएसएसआई- संशोधित दैनिक न्यूनतम वेतन जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षाधीन अवधि के लिए अर्धकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है।

डब्ल्यूआईएसई- संशोधित दैनिक न्यूनतम वेतन जैसा कि समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू अकुशल श्रम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है।

उपरोक्त मुआवजा दावेदार को जी. ओ. संख्या 835 दिनांक 18.12.80 के प्रकाशन दिनांक 23.12.80 के पश्चात किये गये कार्य हेतु कार्य समाप्ति तक देय है।

यह गंभीरता से विवादित नहीं है कि टिप्पणी "दावा स्वीकार किया जाता है" केवल दावे की अनुमति देने के मध्यस्थ के निर्णय के संदर्भ में है, न कि सरकार की ओर से रियायत या स्वीकृति के रूप में। वास्तव में दलीलों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने हर दावे का विरोध किया था और उसकी ओर से कोई रियायत नहीं दी गई थी।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, दावा संख्या ॥ पर मध्यस्थ द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों के वैधानिक संशोधन के कारण, मध्यस्थ ने श्रम वृद्धि के संबंध में निर्णय दिया। इस मद के तहत वृद्धि वास्तव में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुबंध के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन इसके

संदर्भ में सरकार की शिकायत इसलिए नहीं है कि अंपायर ने श्रम के लिए वृद्धि दी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने अनुबंध के तहत प्रदान किए गए के अलावा अन्यथा वृद्धि की अनुमति दी है। मद 35 के तहत अनुबंध प्रदान करता है -

'श्रम के कारण लागत में वृद्धि या कमी की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार त्रैमासिक की जाएगी:

$$V1 = 0.75 \frac{P1}{100} \times R \frac{(i-i)}{10}$$

वी1= श्रम की दरों में परिवर्तन के कारण विचाराधीन तिमाही के दौरान काम की लागत में वृद्धि या कमी।

आर= विचाराधीन तिमाही के दौरान किए गए कार्य का मूल्य रुपये में।

1= उस तिमाही के लिए औद्योगिक श्रमिकों (थोक मूल्य) के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसमें निविदाएं खोली गईं (जैसा कि आंध्र प्रदेश के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो के निदेशक द्वारा नलगोंडा जिले में प्रकाशित किया गया है)।

पी1= श्रम घटकों का प्रतिशत (मद के परिशिष्ट -9 में अनुसूची में निर्दिष्ट)।

i= विचाराधीन तिमाही के लिए औद्योगिक श्रमिकों (थोक मूल्य) के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।

मूल्य समायोजन खंड केवल उस कार्य के लिए लागू होगा जो निर्धारित समय या उसके विस्तार के भीतर किया जाता है, जो ठेकेदार पर लागू नहीं होता है। यहां दिए गए मूल्य समायोजन के अलावा किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।"

सरकार का तर्क यह है कि दोनों फॉर्मूले एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थ ने सहमत फॉर्मूले के तहत गारंटी से कहीं अधिक का फैसला सुनाया। श्री माधव रेड्डी का कहना है कि यह सच है कि ठेकेदार प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य था। वास्तव में अनुबंध में एक प्रावधान होता है जो ठेकेदार के लिए सभी कानूनों, विनियमों, उपनियमों, अध्यादेशों, विनियमों आदि का अनुपालन करना आवश्यक बनाता है। लेकिन यह तथ्य कि ठेकेदार को आवश्यक रूप से मजदूरी की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करना पड़ता था, उसे सरकार से अनुबंध के तहत सख्ती से प्रदान की गई राशि से अधिक किसी भी राशि का दावा करने का अधिकार नहीं था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, आइटम 35 के तहत एक विशिष्ट फॉर्मूला निर्धारित किया गया था, और अंपायर का कार्य उस फॉर्मूले के अनुसार पंचाट देना

था। उनके पास फॉर्मूला बदलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जो उन्होंने किया, जैसा कि पंचाट से देखा जा सकता है।

ठेकेदार की ओर से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थ द्वारा अपनाया गया फॉर्मूला, जैसा कि दावा संख्या II के तहत दिए गए फैसले से देखा जा सकता है, अनुबंध के तहत निर्धारित फॉर्मूले से अलग है। लेकिन श्री के.आर. ठेकेदार की ओर से पेश होने वाले वकीलों में से एक, चौधरी बताते हैं कि अनुबंध में मौजूदा दरों के अनुसार सभी मजदूरी के भुगतान का प्रावधान है और इसलिए, वेतन की बढ़ी हुई दरों और उच्च न्यायालय को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला अपनाकर निर्णय देना मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में था, उनका तर्क है कि पंचाट के संदर्भ में उस दावे के तहत राशि का निर्णय सही है।

हम दावा संख्या IV और VII(4) से अलग-अलग निपटेंगे। लेकिन जहां तक दावा संख्या III, VI और IX का संबंध है, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय यह कहने में सही था कि मध्यस्थ ने उन दावों को देने में अनुबंध के बाहर काम किया। इसी कारण से हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत था, जो उसने दावा संख्या II के संबंध में किया था। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्यस्थ के लिए अनुबंध के बाहर कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है।

ये चार दावे अनुबंध के तहत देय नहीं हैं। अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं है, वास्तव में यह किसी भी वृद्धि के भुगतान पर रोक लगाता है। नापा-स्लैब के लिए दावा संख्या III के तहत या पानी की अतिरिक्त लीड के लिए दावा संख्या VI या नहर ढलानों को समतल करने के लिए दावा संख्या IX या दावा संख्या II के तहत अनुबंध द्वारा निर्धारित फार्मूले की शर्तों के अलावा श्रम शुल्क में वृद्धि। इस निष्कर्ष पर अनुबंध के निर्धारण से नहीं, बल्कि केवल अनुबंध को देखने से पहुंचा जा सकता है। अंपायर ने पूरी तरह से अनुमेय क्षेत्र के बाहर यात्रा की और इस प्रकार उन दावों के तहत पंचाट देने में अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गया। यह उसके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाने वाली त्रुटि है। जीवराजभाई उजामशी शेठ और अन्य बनाम चिंतामनराव बालाजी और अन्य एआईआर 1965 एससी 214 देखें। हम इस मुद्दे पर श्री माधव रेड्डी की दलीलों से पूरी तरह सहमत हैं।

जहां तक दावा संख्या IV और VII(4) का संबंध है, हमें श्री माधव रेड्डी के तर्कों में कोई योग्यता नहीं दिखती। दावा संख्या IV 'मशीनरी के अतिरिक्त किराया शुल्क की वापसी और विभाग मशीनरी के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप मूल्यांकन के लिए भुगतान और भविष्य के लिए दिशा-निर्देश से संबंधित है। हमारे विचार में, इस दावे को मध्यस्थ द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी और उसके निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा

उचित रूप से बरकरार रखा गया था। सरकार, अनुबंध की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा आपूर्ति की गई मशीनरी के खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए अतिरिक्त उच्च शुल्क के लिए ठेकेदार को मुआवजा देने के लिए बाध्य थी।

दावा संख्या VII(4) 'रेत परिवहन' के संबंध में है। मध्यस्थ कहता है-

"जैसा कि मूल निविदा में दर्शाया गया है, समझौते के पृष्ठ 59 पर विवरण (ए) के आइटम नंबर 5 के लिए डीजल तेल की आवश्यकता 0.35 लीटर के रूप में ली जाएगी, न कि 0.035 और तदनुसार मूल्य समायोजन किया जाएगा।"

हमारे विचार में, मध्यस्थ ने ऐसा कहकर सही कहा था और उच्च न्यायालय ने, हमारे विचार से, उचित रूप से इस दावे को सही ठहराया

मध्यस्थ मनमाने ढंग से, अतार्किक रूप से, स्वेच्छाचारिता से या अनुबंध से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। उसका एकमात्र कार्य अनुबंध की शर्तों में मध्यस्थता करना है। अनुबंध के तहत पार्टियों ने उसे जो कुछ दिया है, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि उसने अनुबंध की सीमा से बाहर यात्रा की है, तो उसने अधिकार क्षेत्र के बिना

कार्य किया है। लेकिन यदि वह अनुबंध के मापदंडों के अंदर रहा है और अनुबंध के प्रावधानों का अर्थ लगाया है; उनके पंचाट में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने पंचाट के लिए बताये कारण कारणों में प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटि नहीं की हो।

एक मध्यस्थ जो अनुबंध की स्पष्ट अवहेलना करते हुए कार्य करता है वह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। उसका अधिकार अनुबंध से प्राप्त होता है और मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होता है जो एजेंसी के कानून की एक विशेष शाखा से प्राप्त सिद्धांतों का प्रतीक है (मस्टिल एंड बॉयड्स वाणिज्यिक मध्यस्थता, दूसरा संस्करण, पृष्ठ 641 देखें)। वह कदाचार करता है यदि अपने पंचाट के द्वारा वह समझौते से बाहर किए गए मामलों का निर्णय करता है (देखें हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, खंड II, चौथा संस्करण, पैरा 622) जानबूझकर अनुबंध से हटना न केवल उसके अधिकार की अवहेलना या उसकी ओर से कदाचार को दर्शाता है, बल्कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकता है। कानून या अनुबंध के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना, जिससे उसने अपना अधिकार प्राप्त किया है, पंचाट को खराब कर देता है।

मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र से संबंधित विवाद पंचाट के भीतर का विवाद नहीं है, बल्कि ऐसा विवाद है जिसका निर्णय पंचाट के बाहर किया जाना है। एक अंपायर या मध्यस्थ किसी ऐसे प्रश्न का निर्णय करके अपने

अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता है जो पार्टियों द्वारा उसे नहीं भेजा गया है या किसी प्रश्न का निर्णय अनुबंध के अनुसार नहीं किया गया है। वह यह नहीं कह सकता कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि अनुबंध में क्या कहा गया है। वह इससे बंधा हुआ है। इसे उसका निर्णय स्वीकार करना होगा। वह इसकी सीमा से बाहर यात्रा नहीं कर सकता। यदि उसने ऐसा करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, तो उसका पंचाट रद्द कर दिया जाएगा। जैसा कि लॉर्ड परमूर ने कहा है:-

"..... किसी अंपायर को किसी ऐसे प्रश्न पर खुद के अधिकार क्षेत्र का दावा करने की अनुमति देना असंभव होगा जो प्रस्तुतीकरण के वास्तविक निर्माण पर उसे संदर्भित नहीं किया गया था। एक अंपायर इस तथ्य के विपरीत यह कहकर अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा नहीं बढ़ा सकता कि वह जिस मामले को प्रभावित करता है.. "

पंचाट में प्रथम दृष्टया दिखने वाले मामलों का साक्ष्य यह तय करने के लिए स्वीकार्य है कि क्या मध्यस्थ ने अनुबंध की सीमा से बाहर यात्रा की और इस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। यह देखने के लिए कि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र क्या है, न्यायालय यह देखने के लिए

स्वतंत्र है कि उसके समक्ष कौन सा विवाद प्रस्तुत किया गया था। यदि यह निर्णय से स्पष्ट नहीं है, तो न्यायालय बाहरी स्रोतों का सहारा लेने के लिए खुला है। न्यायालय पक्षों के हलफनामों और दलीलों को देख सकता है, वह समझौते को भी देख सकता है। बंज एंड कंपनी बनाम देवर एंड वेब, [1921] 8 एल एल एल. प्रतिनिधि 436 (के.बी.)।

यदि मध्यस्थ अनुबंध के निर्माण में कोई त्रुटि करता है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में एक त्रुटि है। लेकिन यदि वह अनुबंध के बाहर घूमता है और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटता है, तो वह क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि करता है। ऐसी त्रुटि वह अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर पंचाट के बाहर की सामग्री को देखकर स्थापित कर सकता है। ऐसे मामलों में बाहरी साक्ष्य स्वीकार्य हैं क्योंकि विवाद ऐसा कुछ नहीं है जो अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होता है या अनुबंध के निर्माण पर निर्भर करता है या पंचाट के भीतर निर्धारित किया जाता है। क्षेत्राधिकार के संबंध में विवाद एक ऐसा मामला है जो पंचाट से बाहर है पंचाट में इसके बारे में बाहर कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में, पंचाट की अस्पष्टता को बाहरी साक्ष्य को स्वीकार करके हल किया जा सकता है। इस नियम का तर्क यह है कि विवाद की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे फैसले में दिखाई गई बातों से बाहर और स्वतंत्र रूप से निर्धारित

किया जाना चाहिए। ऐसी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि को पंचाट से संबंधित साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

अलोपी पार्षद एंड संस। लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1960] 2 एससीआर 793; बंज एंड कंपनी बनाम देवर एंड वेब, [1921] 8 एलएल। एल. प्रतिनिधि 436 (के.बी.); क्रिस्टोफर ब्राउन एल.डी. वी. जेनोसंशा/टी ओस्टररेइचिशर, [1954] 1 क्यूबी 8; रेक्स बनाम फ़ुलहम, [1951] 2 के.बी. 1; फाल्किंगहैम बनाम विक्टोरियन रेलवे कमीशन, [1900] ए.सी. 452; रेक्स बनाम ऑल सेंट्स, साउथेम्प्टन, [1828] 7 बी. एंड सी. 785; लाइंग. सन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम ईस्टचीप ड्राइड फ्रूट कंपनी, [961] 1 एलएल। एल. प्रतिनिधि 142, 145 (क्यू.बी.); डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, [1978] 2 एलएल.एल. प्रतिनिधि 223 (सी.ए.); हेमैन बनाम डार्विंग एल.डी., [1942] ए.सी. 356; भारत संघ बनाम किशोरीलाल, एआईआर 1959 एससी 1362; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, [1984] 4 एससीसी 679; जीवराजभाई बनाम चिंतामनराव, एआईआर 1965 एससी 214; गोबर्धन दास बनाम लछमी राम, एआईआर 1954 एससी 689, 692; थावरदास बनाम भारत संघ, एआईआर 1955 एससी 468; ओमानहेन बनाम चीफ ओबेंग, एआईआर 1934 पी.सी. 185, 188; एफ.आर. अबशालोम. लिमिटेड बनाम ग्रेट वेस्टर्न लंदन गार्डन विलेज सोसायटी।

लिमिटेड, [1933] एसी 592 (एचएल) और एम. गोलोडेजव. श्रियर एवं अन्य, [1947] 80 एलएल। एल प्रतिनिधि 647.

मौजूदा मामले में, अंपायर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामले का फैसला किया। उन्होंने अनुबंध की सीमाओं का उल्लंघन किया। वह निर्धारित क्षेत्र से काफी बाहर भटक गया। वह आवंटित कार्य से काफी भटक गए। उनकी गलती अनुबंध को गलत तरीके से पढ़ने या गलत अर्थ निकालने या गलत समझने के कारण नहीं हुई, बल्कि सहमति से अधिक कार्य करने के कारण हुई। यह उनके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाने में एक त्रुटि थी क्योंकि उन्होंने खुद से गलत सवाल पूछा, अनुबंध की अवहेलना की और अपने अधिकार से अधिक का अनुबंध दिया। कई मामलों में, यह पंचाट अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था।

इनमें बताए गए सिद्धांतों को देखें; एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम विदेशी मुआवजा आयोग, (1969] 2 एसी 147) ; पर्लमैन बनाम हैरो स्कूल के रखवाले और गवर्नर, (1979] 1 क्यू.बी. 56; ली बनाम शोमेन गिल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन [1952] 2 क्यू.बी. 329; एम.एल. सेठी बनाम आर.पी. कपूर, एआईआर 1972 एससी 2379; प्रबंध निर्देशक। जे. और के. हस्तशिल्प बनाम एम.जे. गुड लक कार्पेट, एआईआर 1990 एससी 864 और आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। वी. आर. वी. रायनिम, एआईआर 1990

एससी 626; मस्टिल एंड बॉयड की वाणिज्यिक मध्यस्थता, दूसरा संस्करण भी देखें; इंग्लैंड के हेल्सबरी के नियम, चौथा संस्करण, खंड 2

हमारे विचार में, अंपायर ने अनुबंध की सीमाओं और स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करके अनुचित, अतार्किक और मनमौजी तरीके से काम किया, उन दावों को देने में जो अनुबंध के प्रावधानों के पूरी तरह से विरोध में हैं, जिसके लिए उन्होंने उन्हें अनुमति देने में विशिष्ट संदर्भ दिया था, उन्होंने गलत दिशा में काम किया है। और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं और उस अनुबंध की सीमाओं की स्पष्ट रूप से अवहेलना करके खुद का कदाचार किया जिससे उसने अपना अधिकार प्राप्त किया था और इस प्रकार अल्ट्रा फाइन समझौता कार्य किया ।

इन परिस्थितियों में, हम दावा संख्या ॥ के संबंध में छोड़कर अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, ठेकेदार की अपीलें खारिज की जाती हैं; और, दावा संख्या ॥ के संबंध में सरकार की अपीलें स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

जी.एन.

अपीलें खारिज

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री **राजपाल सिंह** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)